

संपादकीय

महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी से बिगड़ रहा सत्ता का समीकरण

पिछली सरकार में काफी उथल-पुथल बनी रही। तब शिवसेना के साथ मिल कर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने पाला बदल लिया और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिल कर महाअंधाड़ी की सरकार बना ली थी। गठबंधन में चुनाव जीत कर बहुमत हासिल करने पर अक्सर मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन जाती है। फिर, गठबंधन धर्म का निर्वाह और सहयोगी दलों के साथ सौहार्दपूर्ण समीकरण बिठाने में कई बार कठिनाई पेश आती है। महाराष्ट्र में भाजपा के सामने भी वही स्थिति है। वहां उसने एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुआई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल कर चुनाव लड़ा था। सबसे अधिक सीटें भाजपा को मिलीं। स्पष्ट बहुमत से महज तेरह सीटें कम। इस लिहाज से मुख्यमंत्री पद पर उसी का हक बनता है। शुरू में एकनाथ शिंदे ने जरूर कुछ दबाव बनाने का प्रयास किया था, मगर आखिरकार उड्होंने भी भाजपा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इस तरह भाजपा के लिए रास्ता साफ हो गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जाने लगा। मगर दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की जा सकी। चुनाव नतीजों के सात दिन बाद भी इस मामले में निर्णय न लिए जा सकने से स्वाभाविक ही तरह-तरह के कथास लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार में काफी उथल-पुथल बनी रही। तब शिवसेना के साथ मिल कर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने पाला बदल लिया और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिला कर महाअंधाड़ी की सरकार बना ली थी। फिर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस में बड़ी टूट हुई और इन दलों के नेताओं ने भाजपा के साथ मिल कर एकनाथ शिंदे की अगुआई में सरकार बना ली थी। सभव है, वहां उलट-फेर की आशंका भाजपा को अब भी सता रही होगी, इसलिए वह नई सरकार के गठन में किसी भी तरह सहयोगी दलों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहती। फिर, जातियों का समीकरण भी उसे साधना है। वह मराठा दबदबे से अलग पिछड़े और दलित वर्ग में पैठ बनाना चाहती है।

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह इन वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, उससे यह कथास स्वाभाविक रूप से लगाया जाने लगा है कि महाराष्ट्र में भी भाजपा कोई हैरान करने वाला फैसला कर सकती है। राजनीति में केवल सरकार बना लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, सरकार के माध्यम से अपने जनाधार का विस्तार करना भी होता है। भाजपा इसी रणनीति पर काम कर रही है। मगर सरकार के गठन में देरी से प्रशासनिक कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मतदाता उन वादों को अमली जापा पहनते देखना चाहते हैं, जो चुनाव प्रचार के समय विजेता पक्ष ने किए थे। प्रशासनिक अमला इंतजार करता रहता है कि नई सरकार निर्देश दे कि उसे किन मसलों को तरजीह देना है और किन मसलों को मुलतवी करना है। महाराष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में शुमार है, इसलिए वहाँ सरकार गठन में हीने वाली देरी का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यह ठीक है कि गठबंधन में संतुलन साधना कठिन होता है, मगर महाराष्ट्र में ऐसी कोई अड़चन नजर नहीं आती। भाजपा को ही अपने असमर्जस से बाहर निकलना है। चूंकि वह बड़ी पार्टी है, उसे सहयोगी दलों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करना और उनके सहयोग का सम्मान करना होगा, तभी महाराष्ट्र की टिकाऊ और भरोसेमंद सरकार बन सकेगी। पहले ही महाराष्ट्र काफी उठापटक झेल चुका है, उसे राजनीतिक स्थायित्व की जरूरत है।

सरकार की यह पहल गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं शोध तक शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पहुंच को आसान बनाएगी। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है जो भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तीकरण के लिए गेम-चेंजर साबित होंगी। इस योजना का लक्ष्य उन संस्थानों के लिए शोध परिक्राओं तक पहुंच का विस्तार करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों देश भर के छात्रों को विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से बन नैशन बन सब्स्क्रिप्शन (ओएनओएस) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता विश्व स्तर पर प्रकाशित हो रहे 13,000 से अधिक ई-जर्नल तक आसान पहुंच हासिल कर सकेंगे। ओएनओएस योजना केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी रहने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर पर सृजित हो रहे ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगी। इससे पहले जर्मनी और उरुग्वे सरकारों ने अनुसंधान सामग्री तक समान राष्ट्रीय पहुंच की शुरुआत की थी। वास्तव में वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है, जब वैश्विक ज्ञान तक पहुंच सुलभ हो जाए। अनुसंधान एवं विकास ही हम सभी के लिए बेहतर जीवन का द्वारा खोलती है। भारत पिछले कुछ वर्षों में श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में काम कर रहा। 15 अगस्त, 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की

मगर विडंबना है कि इस समस्या की गंभीरता और इसके कारणों के बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी नहीं समझा जाता। यहीं वजह है कि अब इस समस्या के बढ़ते दायरे ने व्यापक तबाही के संकेत देने शुरू कर दिये हैं। हालांकि हवा में जहर घुलने से कई तरह की बीमारियों की चपेट में लोगों के आने के तथ्य एक बड़ी युनौती बनते जा रहे हैं और इस हकीकत से मुंह मोड़ना अब संभव नहीं रह गया है। मगर हाल के वर्षों में ज़ंगलों में लगने वाली आग की वजह से हवा में जो प्रदूषण घुल रहा है, उससे भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य परिका 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन में इससे संबंधित जो व्योरा सामने आया है, वह इसकी गंभीरता को रेखांकित करती है। गैरतलब है कि ज़ंगलों और घास के वाली आग और प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियों के वर्ष लगभग साढ़े चार लाख लोगों की जान चल

थी और जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ा था। सरकार की यह पहल गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं शोध तक शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की पहुंच को आसान बनाएगी। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकसित भारत और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तीकरण के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। इस योजना का लक्ष्य उन संसाधनों के लिए शोध पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करना है, जिनके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। यह प्लेटफार्म एक जनवरी, 2025 को शुरू होने वाला है। इस मंच पर एप्लैटिवर साइंस डायरेक्ट (लैंसेट सहित), स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकेपेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, आइईईई, सेज पब्लिशिंग, अमेरिकन कैमिकल सोसायटी, अमेरिकन मैथेमेटिकल सोसायटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैब्रिज

ज्ञान के द

यूनिवर्सिटी प्रेस और बीएमजे जर्नल्स सहित 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत दस अलग-अलग पुस्तकालय संघ हैं, जो अपने प्रशासनिक दायरे में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा अलग-अलग संस्थान अलग-अलग पत्रिकाओं की सदस्यता लेते हैं। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सदस्यता एक महंगा मामला है। ओएनओएस के आरंभ होने से यह बहुत सस्ता हो जाएगा। एक ही मंच पर सारी पत्रिकाएं उपलब्ध होने से शोधार्थियों को भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक सदस्यता पर रुपरेख खर्च डाटाबेस 2017 और के शोध प्रतिशत की औसत (2 भी अधिक पत्रिकाओं स्थान (13 रखता है, अमेरिका (14 लाख जब उत्पादित बात आ (साइटेशन पीछे रह जा स्थान पर

रवाजे से और प्रिंट पत्रिकाओं की विकास लगभग 1,500 करोड़ किए थे। शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तिक्खल के अनुसार इसका वर्ष 2022 के बीच भारत विकाश में लगभग 54 लाख वृद्धि हुई, जो वैश्विक 12 प्रतिशत) के दोगुने से अधिक है। भारत का शोध के प्रकाशन में चौथा लाख अकादमिक पेपर) जो चीन (45 लाख), 44 लाख) और ब्रिटेन (30) के ठीक बाद है, परंतु देश शोध के प्रभाव की तीव्री है, तो उद्धरणों (20) की संख्या में भारत आता है और दुनिया में नैवें आता है। सरकारी धिक्कार टैक फार एक अनुस दुनिया नवाच अनुस कम आफ दस विज्ञा विकास कम अनुस व्यय जबविं प्रतिशत अनुस करने

खोलने की पहल

नीति आयोग और इंस्टीट्यूट कांपिटिवनेस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत का अंथान एवं विकास पर यह खर्च 2011 में सबसे कम है। देश की वायासफलता में एक और बाधा अंथान एवं विकास कार्मियों की संख्या है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट स्ट्रेटिस्टिक्स के अनुसार प्रति लाख आबादी पर केवल 253 नीं या शोधकर्ता हैं, जो सेत राष्ट्रों की तुलना में काफी होते हैं। निजी क्षेत्र का योगदान अंथान एवं विकास पर सकल का 40 प्रतिशत से कम है, क उन्नत देशों में यह 70 प्रति से अधिक है। दुनिया में अंथान एवं विकास पर खर्च के मामले में शीर्ष 2,500 वैश्विक कंपनियों की सूची में केवल 26 भारतीय कंपनियाँ हैं। जबकि चीनी कंपनियों की संख्या 301 है। इस अंतर को प्राथमिकता के आधार पर पाटने की आवश्यकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए उससे सीख लेने में हर्ज नहीं। इजरायल से भी सीख ली जानी चाहिए, जिसने यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। भारत में निजी कंपनियाँ मुख्य रूप से ब्रिटी और विपणन में निवेश करती हैं और अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त संसाधनों का निवेश नहीं करती हैं। यही कारण है कि भारतीय ब्रांड नवाचार नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय निर्माता विश्व स्तर पर अनुकरणीय उत्पाद नहीं बना रहे हैं और विश्व बाजार में चीनी कंपनियों की चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मेक इन ईड़िया के लिए अनुसंधान एवं विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभावान आबादी और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति हैं। जरूरत है तो कच्ची प्रतिभाओं की खान को सही मार्गदर्शन की। वास्तव में एक मजबूत अर्थव्यवस्था होने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है, जो अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है। जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी उतने बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। (लेखक जेन्यू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं।)

दौलत और दिखावे की दौड़ में हाशिये पर संवेदनशीलता, क्या हम असल में रह गए हैं इंसान

कई अभिभावक अपने किशोर होते बच्चे

मनुष्यता को
बचाने की लड़ाई हर
सभ्यता में दर्ज है। वहाँ
से चलते हुए मनुष्य
आधुनिक होते हुए
आज तकनीकी पर
इतना निर्भर हो चला है
कि अपने आपको



अनदेखा मत करो। कोई अगर करीब का परेशान है तो उसे सिर टिकाने के लिए अपना कंधा दो। उसका मन हल्का होने दो। अपनी तरफ से कुछ भी योगदान हो, जिससे आसपास का परिवेश सौहार्दपूर्ण हो, तो ऐसा किया करो। मगर इन बेहद ज़रूरी मुद्दों को खंगालने, संवारने, सुधारने, फैलाने और उस पर विचार करने आदि के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। कई बार बेबसी होती है, कई बार चमक-दमक में फँसने के बाद जरा सरल होकर जीवन की गली से होकर गुजरने का भाव भी पैदा ही नहीं होता। हलांकि संसार को आज संवेदनशील तथा मानवीय भावना के विकास की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मतलबीपन, तंगदिली या आडंबर के खेल में अत्यधिक रमने के कारण हम इस बात पर विशेष या उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना इस संसार को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी होता है। निश्चित रूप से मानव कहलाने योग्य वे ही हैं जो बात नहीं, कर्म करके किसी दुखी के चेहरे पर हँसी और खुशी लाने की सोच रखते हैं। आज तो पाठशाला और पाठ्यक्रम भी इस तरह के कारोबारी हो गए हैं कि पांच साल का बालक भी जल्दी-जल्दी रूपए कमाने के सपने देखता है। किसी ने कितनी प्यारी बात कह दी है कि ऐसा कोई विद्यालय हो तो बताना, जहां बच्चों को पैसा कमाने की मशीन नहीं, संस्कार, सुविचार और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया जाता हो। आज के असुरक्षित सामाजिक-आर्थिक परिवेश में अभिभावक भी अपनी संतान को चट पढ़ाई और पट दौलत का ही सूत्र रटाए जाते हैं। यह नहीं सोचते कि अपनी औलाद को ऐसा बनाया जाए, जहां मन और आत्मा अच्छे विचारों के आधार पर पुष्टि और पल्लवित हो। कितने ही अभिभावक अपने किशोर होते बच्चे से यह कहते हुए मिल जाते हैं कि बेटा तुम किसी पर भरोसा न करनाज किसी की बात में मत आना। इस धरती पर तुम ही मनुष्य हो, बाकी की मनुष्यता तो खो गई है। मगर यह सब रटाते हुए अभिभावक मन ही मन यह कामना भी करते रहते हैं कि उनके बच्चे पर सारा संसार भरोसा करे। उनके बच्चे को सबसे ईमानदार और सच्चा मान ले। यह कैसी उलटबांसी है। जिस पेंसिल से वे बाकी लोगों का खराब छवि बनाकर दिखा रहे हैं, जरा उसी से अपनी शक्ति भी बनाकर ठीक से देख लेते। इसीलिए यह जगत विरोधाभास का शिकार हो रहा है। हम सब अच्छी और सुखद दुनिया तो चाहते हैं, लेकिन उसे तैयार करने के लिए कौन, कैसे बीड़ा उठाएगा, यह सबाल दूसरे के पाले में ही जाता हुआ प्रतीत होता है। 'येन-केन-प्रकारेण मेरे पास पर्यास दौलत आ जाए, चुपचाप से छल कपट कर लूँग मेरा मतलब सिद्ध हो जाए, मुझे लाइन में इंतजार न करना पड़ जाएँ मेरे घर के सामने कचरा न होज मैं बाहर से अच्छा और संभ्रांत नजर आऊँ...' इस तरह के चिंतन मनन और ऐसी मनोवृत्ति ने ही आज की सुविधाभोगी पांडी को भर-भर कर अवसाद, कुंठ और उदासी दी है। एक बार फिर से हर घर में कबीर को सुनना चाहिए कि मानव अपने लालच के फंदे में फंसी वह मछली है जो जल में रहकर भी प्यासी है। यह अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन के लिए समय निकालने का समय है। हमें जाग जाना चाहिए। हम किस तरह की दिनचर्या में जी रहे हैं। मतलबीपन को अपनी सोच से उखाड़ फेंकने का संकल्प आज ही लेना चाहिए। इसे हर समय याद करने की जरूरत है कि मनुष्य वही है, जो मनुष्य के लिए मरे।

ज्ञान के दरवाजे खोलने की पहल

वर्सिटी प्रेस और बीमजेर रॉल्स सहित 30 अंतरराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा प्रकाशित 13,000 अंकाएं उपलब्ध होगी। वर्तमान में ऐन्स मंत्रालयों के अंतर्गत दस नग-अलग पुस्तकालय संघ हैं, अपने प्रशासनिक दायरे में उच्च शक्ति संस्थानों के लिए पत्रिकाओं को पहुंच प्रदान करते हैं। इसके बाबा अलग-अलग संस्थान नग-अलग पत्रिकाओं की स्वता लेते हैं। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सदस्यता एक महंगा बला है। ओएनओएस के आरंभ से यह बहुत सस्ता हो जाएगा। इस ही मंच पर सारी पत्रिकाएं उपलब्ध होने से शोधार्थियों को बढ़करना भी नहीं पड़ेगा। एक आंकड़े अनुसार भारत ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रिकाओं की सदस्यता पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे। शोध अंतर्वृष्टि डाटाबेस स्किवल के अनुपार 2017 और 2022 के बीच भारत के शोध प्रकाशन में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक औसत (22 प्रतिशत) के दोगुने से भी अधिक है। भारत का शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन में चौथा स्थान (13 लाख अकादमिक पेपर) रखता है, जो चीन (45 लाख), अमेरिका (44 लाख) और ब्रिटेन (14 लाख) के ठीक बाद है, पंतु जब उत्पादित शोध के प्रभाव की बात आती है, तो उद्धरणों (साइटेशन) की संख्या में भारत पीछे रह जाता है और दुनिया में नौवें स्थान पर आता है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फार कापिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत का अनुसंधान एवं विकास पर यह खर्च दुनिया में सबसे कम है। देश की नवाचार सफलता में एक और बाधा अनुसंधान एवं विकास कर्मियों की कम संख्या है। यूरेस्को इंस्टीट्यूट आफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्रति दस लाख आबादी पर केवल 253 विज्ञानी या शोधकर्ता हैं, जो विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। निजी क्षेत्र का योगदान अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह 70 प्रतिशत से अधिक है। दुनिया में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में शोधी 2,500 वैश्विक कंपनियों की सूची में केवल 26 भारतीय कंपनियां हैं। जबकि चीनी कंपनियों की संख्या 301 है। इस अंतर को प्राथमिकता के आधार पर पाठने की आवश्यकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए उससे सीख लेने में हर्ज नहीं। इजरायल से भी सीख ली जानी चाहिए, जिसने यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। भारत में निजी कंपनियां मुख्य रूप से बिक्री और विपणन में निवेश करती हैं और अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त संसाधनों का निवेश नहीं करती हैं। यही कारण है कि भारतीय ब्रांड नवाचार नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय निर्माता लिए अनुसंधान एवं विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभावान आबादी और मितव्यी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति हैं। जरूरत है तो कच्ची प्रतिभाओं की खान को सही मार्गदर्शन की। वास्तव में एक मजबूत अर्थव्यवस्था होने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है, जो अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है। जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी उतने बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं।)

प्रदूषण की आग से घुट रहीं विकासशील देशों की सांसें, इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार?

A blurred background image of a city street at night, showing lights from buildings and trees.

ठोस कदम उठाना जरूरी नहीं समझा जाता। यही वजह है कि अब इस समस्या के बढ़ते दारये ने व्यापक तबाही के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि हवा में जहर घुलने से कई तरह की बीमारियों की चपेट में लोगों के आने के तथ्य एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और इस हकीकत से मुंह मोड़ना अब संभव नहीं रह गया है। मगर हाल के वर्षों में जगलों में लगने वाली आग की वजह से हवा में जो प्रदूषण घुल रहा है, उससे भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य परिक्रमा 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन में इससे संबंधित जो ब्लोगर सामने आया है, वह इसकी गंभीरता को रेखांकित करने के लिए काफी है। गौरतलब है कि जंगलों और धारा के मैदानों में लगने वाली आग और प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियों के कारण हर वर्ष लगभग साढ़े चार लाख लोगों की जान चली जाती है। इनमें नब्बे फासद से ज्यादा मौत निम्न और मध्यम आयवग वाले देशों में होती है। अध्ययन में आशंका जारी रखी है कि जंगल में आग की घटनाओं में बढ़ोतारी के साथ-साथ मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होता जाएगा। ऐसी समस्या से निपटने के लिए विकासित देशों की ओर से विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन समझदृश देश हर ऐसे मौके पर अपनी जिम्मेदारी से पलला झाड़ लेते हैं। हैरानी की बात है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में चरम विकास के दौर में भी जंगल में आग की घटनाओं से पार पाना एक चुनौती बनी रही है। सबाल है कि जब तक इस समस्या पर प्राथमिकता के साथ काम नहीं किया जाएगा, तब तक इसके हल का रास्ता निकालना कैसे संभव होगा !

अपने सामने की
सड़क तक बढ़ा लिए
हैं। पिछली जनगणना
के अनुसार देश के
सभी राज्यों और केंद्र
शासित प्रदेशों में

लगभग 6.40 लाख गांव और 7,935 शहर हैं। यहां निवास करने वाली जनता को स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए होता है। अधिकतर समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं की होती है। अनेक समस्याएं बहुत साधारण होती हैं, लेकिन उनका समाधान न होने से जनता आक्रोशित हो जाती है और प्रायः मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को उत्तरदायी मानती है।

विकास के नाम पर मिली करोड़ों की धनराशि का दुरुपयोग

शहरों की अनगिनत समस्याओं का तो कहना ही क्या? राजन और जीविकोपार्जन के लिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। शहरों की बेतहाशा बढ़ती आबादी से बेतरतीब होते वासीय क्षेत्र अतिक्रमण को जन्म दे रहे हैं। नगर निकाय ला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस पर ध्यान देते। औसत जनता और दुकानदार दोनों ने अपने मकान और दुकान अपने सामने की सड़क तक बढ़ा लिए हैं। पिछली गणना के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित शॉप में लगभग 6.40 लाख गांव और 7,935 शहर हैं। यहाँ वास करने वाली जनता को स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए होता है। अधिकतर समस्याओं समाधान की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और पालिकाओं की होती है। अनेक समस्याएं बहुत साधारण होती हैं, लेकिन उनका समाधान न होने से जनता आक्रोशित होती है और प्रायः मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को उत्तरदायी माननी इसका नतीजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतान पड़ता है। अत्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश ग्राम स्वराज की पथरणा के पुरोधा थे, लेकिन संविधान बनाते समय उसे प्रकार नहीं किया गया। 1992 में संविधान के 73वें और वें संशोधनों द्वारा ग्रामीण स्तर पर पंचायत और शहरी स्तर नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक मान्यता एवं अधिकार दिए गए, जिससे गांधी और जेपे के सपने साकार हो सकें, किंतु उन संवैधानिक संशोधनों के 32 वर्षों बाद भी स्थानीय कारों ऐसा कुछ नहीं कर पाइ है, जिससे ग्रामीण और शहरी जनता को राहत मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 243(छ) और अनुच्छेद 243(ब) क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक-विकास और सामाजिक न्याय के लिए जनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार देते हैं। वंधान की अनुसूची-11 पंचायतों को 28 और नगर निकायों को 18 क्षेत्रों में काम करने का अधिकार देती है। खिर इसके बाद भी शहरों और गांवों की समस्याएं क्यों नहीं जा रही हैं? पंचायतों और नगर पालिकाएं केंद्र सरकार, य सरकार और कुछ बाह्य स्रोतों से पर्याप्त धन प्राप्त कर रही आज छोटी-छोटी पंचायतों को भी विकास के नाम पर

